पहले पड़ोसी देश : एक प्रश्न

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) से संबंधित है।

द हिन्दू

लेखक - सुहासिनी हैदर (संपादक)

01 दिसंबर, 2018

''एक बेहतर पहल के प्रयास में, मोदी सरकार द्विपक्षीय संबंधों में अपने आक्रामक रुख से दूर जाने का प्रायस कर रही है।''

नवंबर के मध्य में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव के नए राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह के शपथ ग्रहण में भाग लेने के लिए पहुंचे, तो मालदीव भी उन सूचियों में शामिल हो गया, जहाँ श्री मोदी ने पहली बार यात्रा की है। श्री मोदी की यह यात्रा दक्षिण एशियाई देश मालदीव की पहली यात्रा थी, जहाँ वे अभी तक अपने कार्यकाल में नहीं गये थे और साथ ही पिछले सात वर्षों में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा की गयी यह पहली यात्रा थी।

हालाँकि, श्री मोदी ने वर्ष 2015 में मालदीव की यात्रा की योजना बनाई थी, लेकिन मजबूत विरोध के बाद उन्हें अचानक अपनी यात्रा की योजना को रद्द करना पड़ा। हालाँकि, इनकी पहली यात्रा, जो सफल नहीं हो सकी, मई 2014 में अपने स्वयं के शपथ ग्रहण समारोह में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) के नेताओं को आमंत्रित करने के बावजूद पूरा नहीं हो सकी। देखा जाये तो श्री मोदी ने पहली बार किसी अन्य नेता के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया है। तथ्य यह भी है कि उन्होंने मंच पर जाने के बजाए दर्शकों के भीड़ में खड़े रहने का विकल्प चुना, जो मोदी सरकार की तरफ से नई सॉफ्ट पड़ोस नीति का एक संकेत मालूम पड़ता है।

वर्ष 2018 में

चालू वर्ष में सामान्य रूप से मोदी सरकार मालदीव के साथ व्याप्त असहमतियों को दूर करके इस क्षेत्र में अपनी पहुँच बढ़ाने में सफल हुई है। इस क्षेत्र में असहमतियों के कारण भारत रूस और चीन जैसे प्रमुख शक्तियों के साथ संबंधों को बेहतर बनाने के प्रयास में लगा हुआ है। लेकिन जहाँ एक तरफ भारत के चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ श्री मोदी के 'वुहान शिखर सम्मेलन' और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ 'सोची रिट्रीट' पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है, तो वहीँ दूसरी तरफ उसे पड़ोसी देशों के साथ बेहतर संबंध स्थापित करने पर विशेष ध्यान देना चाहिए।

नेपाल के साथ, 2015 की नाकाबंदी के बाद से सरकार की चाल 'कठिन प्यार' (tough love) नीति से स्पष्ट रूप से बदल गई थी। फिर, सरकार को प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली को सत्ता से बाहर करने के अलावा कुछ और नहीं चाहिये था। हालाँकि, 2018 में, जब श्री ओली को भारत विरोधी अभियान के बावजूद फिर से निर्वाचित किया गया, तो फिर मोदी सरकार ने वहाँ पहुँचने में समय बर्बाद नहीं किया और एक अपरंपरागत कदम उठाते हुए, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को काठमांडू भेजा गया। इसके बाद से, श्री ओली को दिल्ली में आमंत्रित किया गया और श्री मोदी ने नेपाल में दो दौरे किए हैं और साथ ही दिसंबर में 'विवाह पंचमी' त्यौहार का हिस्सा बनने के लिए भी हामी भरी गयी है। 2018 में यात्राओं की आवृत्ति तीन पिछले वर्षों के विपरीत है।

मालदीव में, अब्दुल्ला यामीन ने जब अपने शासन के दौरान आपातकाल की घोषणा की थी, तो नई दिल्ली ने उन्हें सैन्य रूप से धमकी देने का कोई प्रयास नहीं किया। इसके बाद जब श्री यामीन आगे बढ़े और अपने यहाँ हजारों नौकरी तलाशने वाले, नौसेना और भारतीय सैन्य कर्मियों को वीजा देने से इंकार कर दिया, तो नई दिल्ली की प्रतिक्रिया बस इतनी सी थी कि हर देश को अपनी वीजा नीति तय करने का अधिकार है।

भूटान (पूरा हो चुका है) और बांग्लादेश (दिसंबर में होने वाला है) के साथ-साथ श्रीलंका में चल रहे राजनीतिक संकट के चुनावों के साथ, भारत ने कोई सार्वजनिक राजनीतिक बयान जारी नहीं किया। इस साल की शुरुआत में, सरकार ने बांग्लादेश के विपक्ष के प्रतिनिधि मंडल को दिल्ली आने और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) - सम्बद्ध थिंक टैंकों में बोलने की इजाजत दी, हालाँकि बाद में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के लिए ब्रिटिश क्यूसी वकील को निर्वासित कर दिया गया।

शायद इस वर्ष सबसे बड़ा नीतिगत बदलाव काबुल में अशरफ घनी सरकार को रियायत के रूप में किया गया था। तालिबान के साथ जुड़ने से इंकार करने के दो दशकों से अधिक समय बीत जाने के बाद, नवंबर में भारत ने मॉस्को सम्मेलन में राजदूत भेजे, जहाँ तालिबान के प्रतिनिधि मौजूद थे। यू.एस. ने मॉस्को में एक राजनयिक को 'पर्यवेक्षक' के रूप में भेजने का फैसला किया, लेकिन इस क्षेत्र में पूर्व राजदूतों के भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने इस कार्यक्रम में गैर-आधिकारिक 'भागीदारी' का प्रतिनिधित्व किया। बदलाव स्पष्ट था।

इससे पहले, सरकार इस प्रक्रिया से अलग रहती थी, इसका मानना था कि अफगानिस्तान से बाहर कोई भी बैठक 'अफगान-स्वामित्व वाली और अफगान-नेतृत्व वाले समाधान' पर खतरा है। हालाँकि, रूसी सरकार द्वारा उच्च स्तर के आउटरीच द्वारा स्थिति में परिवर्तन को अंततः हासिल किया गया, जिसने सम्मेलन को एक बड़ी राजनयिक सफलता के रूप में पेश किया और रही बात भारत की, तो इसकी भागीदारी को राष्ट्रपति घनी ने खुद दूर कर दिया था। सितंबर के मध्य में दिल्ली की यात्रा के दौरान उन्होंने तालिबान के साथ वार्ता का समर्थन करने के लिए एक मजबूत मुद्दा बनाया था।

करतारपुर लिंक

इस संदर्भ में, सरकार के नवीनतम बदलाव को देखना आवश्यक है। इस सप्ताह पाकिस्तान में अपने दो केंद्रीय मंत्रियों को करतारपुर गलियारे के भूमि पूजन समारोह में शामिल होने के लिए भेजना, संभवत: भारत की सॉफ्ट पॉवर नीति को दर्शाता है।

सितंबर 2016 में उड़ी हमले के बाद से किसी भी भारतीय मंत्री ने पाकिस्तान का दौरा नहीं किया है और इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र में विदेश मंत्री की वार्ता रद्द करने के बाद, यह माना गया कि सरकार इस्लामाबाद में नई सरकार के साथ समझौता प्रस्तावों का पालन नहीं करेगी। यह भी महत्वपूर्ण है कि बीजेपी और प्रधानमंत्री ने पिछले साल के विधानसभा चुनावों के दौरान पाकिस्तान चुनावों के मौजूदा दौर में पाकिस्तान को चुनावी मुद्दा नहीं चुना है।

हालाँकि, एक भारत द्वारा अपनी आक्रामक नीति को दूर रखने की पहल का यह मतलब नहीं है कि भारत, यू.एस.-चीन प्रतिद्वंद्विता के प्रति अब गंभीर नहीं है।

GS World टीम...

दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)

- दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (दक्षेस) दक्षिण एशिया के आठ देशों का आर्थिक और राजनीतिक संगठन है। इसकी स्थापना 8 दिसम्बर, 1985 को भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान द्वारा मिलकर की गई थी। अप्रैल 3, 2007 में संघ में 14वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान इसका आठवां सदस्य बन गया।
- सार्क दक्षिण एशियाई देशों तक ही सीमित है और आज कुल आठ देशों का सदस्य हो गया है, इसके अलावा कुछ अन्य देशों जैसे म्यांमार, जापान, ऑस्ट्रेलिया, चीन, दक्षिण कोरिया, ईरान, मॉरीशस और यूरोपीय संघ को सार्क के पर्यवेक्षकों का दर्जा का भार दिया गया है। इनमें सबसे बड़ा देश भारत और सबसे छोटा देश मालदीव है।

सार्क की पृष्ठभूमि

- यह 1980 में वापस आ गया था, जब दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय राजनीतिक और आर्थिक सहयोग की अवधारणा को पहले सोचा था। बांग्लादेश के पूर्व अध्यक्ष जियाउर रहमान ने 2 मई, 1980 को सार्क के बारे में औपचारिक प्रस्ताव दिया था। ढाका और अफगानिस्तान में पहला सार्क शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। जो एकमात्र नया सम्मेलन है जो कि सार्क की स्थापना के बाद हुआ है।
- सार्क विश्व के 3%, दुनिया की जनसंख्या का 21% और 2015 तक की वैश्विक अर्थव्यवस्था का 9.12% समझौता करता है। संगठन विकास अर्थशास्त्र और क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा देता है। उसने 2006 में दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र (सेफ्टा) का शुभारंभ किया। इससे पहले 1995 में स्थापित इस एसएपीटीए से पहले सेफ्टा का मार्ग प्रशस्त हुआ था। सार्क संयुक्त राष्ट्र में एक पर्यवेक्षक के रूप में स्थायी राजनयिक संबंध रखता है और यूरोपीय संघ सहित बहुपक्षीय संस्थाओं के साथ संबंध विकसित करता है।

संगठन के उद्देश्य

- सार्क का मुख्य उद्देश्य दक्षिण एशियाई देशों के लोक कल्याण के साथ-साथ लोगों के जीवन यापन के गुणवत्ता में सुधार लाना है।
- आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास जैसे क्षेत्र में तेजी लाना और सभी व्यक्तियों को आत्मसम्मान के साथ उन्हें रहने और उन्हें अपनी क्षमता का अहसास दिलाकर उन्हें अवसर प्रदान करना है।
- दक्षिण एशियाई देशों के बीच सामूहिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना और उन्हें मजबूती प्रदान करना।
- दक्षिण एशियाई लोगों में आपसी विश्वास को बढ़ाना और एक-दूसरे की समस्याओं का समाधान करने के लिए बढ़ावा प्रदान करना।
- आर्थिक, सांस्कृतिक, तकनीकी, नस्लीय और वैज्ञानिक जैसे क्षेत्रों में सक्रिय सहयोग और आपसी सहयोग को बढ़ावा देना है।
- अन्य विकासशील देशों के साथ मिलकर उन्हें सहयोग प्रदान करना है।
- सार्क का लक्ष्य है कि वह अंतर्राष्ट्रीय मंचों और क्षेत्रीय संगठन के साथ मिलकर मदद करे।
- दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग पर इस घोषणा को 1983 में नई दिल्ली में विदेश मंत्रियों द्वारा अपनाया गया। बैठक के दौरान मंत्रियों ने नौ सहमत क्षेत्रों, अर्थात् कृषि, ग्रामीण विकास, दूरसंचार, मौसम, स्वास्थ्य और जनसंख्या क्रियाएँ, परिवहन, डाक सेवा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और खेल, कला और संस्कृति में एकीकृत कार्ययोजना (IPA) की शुरुआत की। सार्क का मुख्य उद्देश्य मानव संसाधन, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और कृषि के क्षेत्र का विकास करना है और साथ ही जनसंख्या और स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दों और परिवहन सुविधाओं के सुधार का समाधान करना है।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:-

   1. करतारपुर गलियारा भारत का पाकिस्तान के साथ 'कठित प्यार' (Tough Love) नीति को दर्शाता है।
   2. ''सोची रिट्रीट' में प्रधानमंत्री मोदी, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन तथा चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बैठक हुई।

   उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

   (a) केवल 1 (b) केवल 2

   (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्रश्न: हाल ही में मालदीव में हुए सत्ता परिवर्तन के पश्चात् भारतीय प्रधानमंत्री का मालदीव के राष्ट्रपति की सपथ समारोह में शामिल होना एक सफल कूटनीतिक बढ़त के रूप में देखा जा रहा है, मालदीव के विशेष संदर्भ में भारत की पड़ोस नीति का वर्णन करे।

(250 शब्द)

नोट : 30 नवम्बर को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(a) होगा।

GS World
Committed To Excellence